



पंजाब और हिमाचल का संपर्क टूटा,
पठानकोट-डलहोजी-चंदा नेशनल हाईवे बंद

गण्डीय हिन्दी दैनिक

लोकशक्ति



दिल्ली में बारिश के साथ हुई सुबह
शुरुआत, उत्तराखण्ड में रेड अलर्ट

RNI Regn. No.7789/1964

वर्ष-61 > अंक - 230

रायपुर बुधवार 13 अगस्त 2025 विक्रम संवत् 2082

पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रु.

डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

18541 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी

मोदी कैबिनेट का निर्णय : चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, यूपी में लखनऊ मेट्रो का होगा विस्तार

नईदिल्ली, एजेंसी



दी है।

क्या बनेगा यहाँ? इन यूनिट्स में मिसाइल, डिफेंस उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs), फास्ट चार्जर, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर में इसेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के चिप और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेंगे। अब हमें चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन यूनिट्स से सीधे तौर पर 2034 से ज्यादा कुशल लोगों को नैकरिया मिलेंगी और हजारों अप्रत्यक्ष रोजारा भी पैदा होंगे। भारत में दुनिया की सबसे एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आयी और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लोगेंगी। यह फैसला भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स लगाने को मंजूरी दे रहा है।

कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा विकास के लिए उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs), फास्ट चार्जर, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर में इसेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के चिप और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेंगे। अब हमें चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन यूनिट्स से सीधे तौर पर 2034 से ज्यादा कुशल लोगों को नैकरिया मिलेंगी और हजारों अप्रत्यक्ष रोजारा भी पैदा होंगे। भारत में दुनिया की सबसे एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आयी और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लोगेंगी। यह फैसला भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरी देता है।

एक ग्रोबल हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पथर है।

फैसला नंबर 2: अरुणाचल के पहाड़ों में बनेगा विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मिलेंगी 700 मेगावाट बिजली

कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा विकास के लिए उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs), फास्ट चार्जर, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर में इसेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के चिप और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेंगे। अब हमें चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन यूनिट्स से सीधे तौर पर 2034 से ज्यादा कुशल लोगों को नैकरिया मिलेंगी और हजारों अप्रत्यक्ष रोजारा भी पैदा होंगे। भारत में दुनिया की सबसे एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आयी और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लोगेंगी। यह फैसला भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरी देता है।

फैसला नंबर 3: 'नवाबों के शहर' को मिली मेट्रो की नई सौगत, पुराने लखनऊ का सफर होगा आसान

कैबिनेट का तीसरा फैसला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए है। लखनऊ के लिए उपयोग होने वाले घोषणा की कि सिंधु जल समझौते रह हो चुका है और अब सिंधु नदी का पानी भारतीय किसानों के लिए उपयोग होगा। यह बयान पाकिस्तान के सेना प्रमुख असिम मुनीर के अमेरिका में दिए गए उस बयान के जबाब में आया, जिसमें उन्होंने सिंधु समझौते को लेकर भारत को धमकी दी थी। शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ मुलाकात के दैरान यह बताया कि याचिका खिरिंग करते हुए कहा, यह तय किसानों के काम आएगा, यह तय फैसला है।

'हमारा पानी हमारे किसानों के काम आएगा, यह तय फैसला है'

शिवराज ने कहा, 'पड़ोसी अमेरिका में किसानों के साथ मुलाकात के दैरान यह बताया कि याचिका खिरिंग करते हुए कहा, यह तय किसानों के काम आएगा, यह तय फैसला है।'

बिजली पैदा करेगा।

किसे मिलेगा फायदा?

राज्य में बिजली की सप्लाई सुधरेगी और उसे 12% बिजली मुफ्त में मिलेगी। यह बनने वाली बिजली नेशनल ग्रिड को नियंत्रित करने में भी मदद करेगी। प्रोजेक्ट के लिए 32 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और पुल बनेंगे, जिनका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। साथ ही, अस्पताल, स्कूल और बाजार जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। यह प्रोजेक्ट न केवल देश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा देगा, बल्कि अरुणाचल प्रदेश जैसे स्थानों पर निर्भर थे। लैंकिन अब यह तस्वीर बल्लभ बनाने वाली है। कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा विकास के लिए उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs), फास्ट चार्जर, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर में इसेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के चिप और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेंगे। अब हमें चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन यूनिट्स से सीधे तौर पर 2034 से ज्यादा कुशल लोगों को नैकरिया मिलेंगी और हजारों अप्रत्यक्ष रोजारा भी पैदा होंगे। भारत में दुनिया की सबसे एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आयी और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लोगेंगी। यह फैसला भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरी देता है।

कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा विकास के लिए उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs), फास्ट चार्जर, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर में इसेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के चिप और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेंगे। अब हमें चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन यूनिट्स से सीधे तौर पर 2034 से ज्यादा कुशल लोगों को नैकरिया मिलेंगी और हजारों अप्रत्यक्ष रोजारा भी पैदा होंगे। भारत में दुनिया की सबसे एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आयी और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लोगेंगी। यह फैसला भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरी देता है।

कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा विकास के लिए उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs), फास्ट चार्जर, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर में इसेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के चिप और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेंगे। अब हमें चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन यूनिट्स से सीधे तौर पर 2034 से ज्यादा कुशल लोगों को नैकरिया मिलेंगी और हजारों अप्रत्यक्ष रोजारा भी पैदा होंगे। भारत में दुनिया की सबसे एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आयी और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लोगेंगी। यह फैसला भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरी देता है।

कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा विकास के लिए उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs), फास्ट चार्जर, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर में इसेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के चिप और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेंगे। अब हमें चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन यूनिट्स से सीधे तौर पर 2034 से ज्यादा कुशल लोगों को नैकरिया मिलेंगी और हजारों अप्रत्यक्ष रोजारा भी पैदा होंगे। भारत में दुनिया की सबसे एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आयी और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लोगेंगी। यह फैसला भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरी देता है।

कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा विकास के लिए उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs), फास्ट चार्जर, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर में इसेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के चिप और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेंगे। अब हमें चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन यूनिट्स से सीधे तौर पर 2034 से ज्यादा कुशल लोगों को नैकरिया मिलेंगी और हजारों अप्रत्यक्ष रोजारा भी पैदा होंगे। भारत में दुनिया की सबसे एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आयी और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लोगेंगी। यह फैसला भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरी देता है।

कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा विकास के लिए उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs), फास्ट चार्जर, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर में इसेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के चिप और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेंगे। अब हमें चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन यूनिट्स से सीधे तौर पर 2034 से ज्यादा कुशल लोगों को नैकरिया मिलेंगी और हजारों अप्रत्यक्ष रोजारा भी पैदा होंगे। भारत में दुनिया की सबसे एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आयी और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लोगेंगी। यह फैसला भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ज़रूरी देता है।

कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला ऊर्जा विकास के लिए उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs), फास्ट चार्जर, मोबाइल फोन और डेटा सेंटर में इसेमाल होने वाले अलग-अलग तरह के चिप और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनेंगे। अब हमें चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी सौगत, सीधे खातों में बीमा राशि का भुगतान

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू से किसानों के खातों में बीमा राशि का डिजिटल भुगतान किया।

35 लाख किसानों को 3,900 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिली।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में रहे गैजूद।

पीआईबी

किसान कल्याण प्रतिबद्धता सिद्ध करते हुए आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के झुंझुनू से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत डिजिटल राशि का भुगतान किया। करीब 35 लाख किसानों के खातों में 3,900 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राजमंत्री श्री भारीपूर्ण चौधरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, मौजूद हों। बड़ी संख्या में किसानों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। विभिन्न



राज्यों के लाखों किसान व लाभार्थी वर्तुल माध्यम से समारोह से जुड़े हैं। इस अवसर पर सर्वान्धित करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक अन्धुत भारत का निर्माण हो रहा है। राजस्थान को जल्द ही यमुना, चंबल के साथ-साथ सिंधु नदी का पानी भी मिलने वाला है। किसानों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। विभिन्न

मजबूती से बदला लिया गया। 'ऑपरेशन सिंटूर' के माध्यम से आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। भारत ने अपनी क्षमता से निर्णय लिया। जब पाकिस्तान ज़ुका और शरण में आया तब हमारी ओर से कारबाई रोकी गई।

श्री चौहान ने कहा कि पहले कि सरकार द्वारा

फसल बीमा की राशि पूरी तरह सीधे खातों में भर्ती होने के बाद ही दी जाती थी लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुरानी सारी योजनाओं को निरस्त करते हुए ऐसी बीमा योजना बनाई कि जिसके अंतर्गत एक गांव क्या एक किसान की भी आर परसल बर्बाद हुई तो बीमा की राशि दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मात्र एक योजना ही नहीं बल्कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों की जिंदगी सुखद बनाने का कार्य कर रही है। पौरे चार लाख करोड़ रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के खातों में वितरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2016 में शुरुआत से अब-तक 2 लाख 12 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं। खाद की सब्सिडी में भी सरकार ने बड़े स्तर पर किसानों के मदद पहुंचाने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज यूरिया की 45 किलो की एक बोरी किसानों को 266 रुपये में मिलती है, इयकी असली कीमत 1,633 रुपये 24 पैसे है। 266 रुपये से ऊपर की सभी राशि का वहन सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाता है। डीएपी की 50 किलो की बोरी किसानों को 1,350 रुपये में मिलती है, जिसकी असली कीमत है 3,100 रुपये। अब-तक 14 लाख

हजार करोड़ रुपये सर्वे सहते खाद के लिए पर्टिलाइजर कंपनियों को दिए जा चुके हैं। अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी केंद्रीय मंत्री ने जित्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा एमएसपी के दाम बढ़ाने का भी काम किया गया है। किसानों की लागत में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर ही एमएसपी तथ करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने 2,000 रुपये प्रति किंटल मूल खरीदारों का निर्णय लिया। किसानों के खातों में 43 लाख 87 हजार करोड़ रुपये डाले गए हैं। बाजार हृतक्षेप योजना (MIP) के तहत भी किसानों को दूसरे राज्यों में माल बेचने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें परिवहन की लागत सरकार बहन करती है।

किसानों के परादे के लिए नई-नई योजनाएं बनाने का काम किया जा रहा है।

वायरस अटैक की स्थिति में यदि किसानों द्वारा जानकारी सज्जा की जाएगी या मारा एक फेटो के जरिए भी सुचना दी जाएगी, तो मदद के लिए वैज्ञानिकों की टीम तुरंत किसानों के पास गांव पहुंचेगी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खरीफ के फसल के बाद अब खबी की फसल के लिए भी 'वैज्ञानिकों की टीम किसानों के गांव-गांव जाएगी और उन्हें खेती व शोध की सभी जानकारी देगी। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि अब भारी कृषि अनुसंधान खेती और किसानों की मांग पर आधारित होंगे। खेती की वर्तमान जरूरत के अनुसार ही वैज्ञानिकों को अनुसंधान करने के लिए उन्हें वैज्ञानिकों को कहा गया है।

कृषि मंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि देश का सौभाग्य है कि हमें श्री नरेन्द्र मोदी के लिए भी प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला है। गश्त को समोनेरि खेते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि देश के किसानों से हिंडों से समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए उन्हें व्यक्तिगत शक्ति ही क्यों ना उठानी पड़े। इस बड़े फैसले ने दुनिया के सामने भारत की मजबूत छवि स्थापित की है।



राज्यों में स्वतंत्रता दिवस परेड के लिए रिहर्सल के दौरान सुरक्षाकर्मी।



जम्मू-कश्मीर के जम्मू जिले में अल्पनूर के पास बारिश के कारण हुए भूखलन के कारण जम्मू-पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अवरुद्ध होने के बाद मरम्मत कार्य जारी है।

ब्रह्माकुमारीज राजनांदगांव द्वारा 24 अगस्त को विशाल रक्तदान शिविर

राजनांदगांव -



युवा संकल्प लोकतंत्र रक्षकों के वंशजों की आत्मनिर्भरता की दिशा में मिशन : उपासने

लोकतंत्र रक्षक संघ की पहल, युवाओं को कौशल विकास, उद्यगिता और दोग्रागार के अवसर;

अन्य राज्यों में भी लागू होगा मॉडल उपासने

पीआईबी

के नए भवन ज्ञान मानसरोवर में भी 24 अगस्त रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा जिसमें लिंगभन्द 100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिविर प्राप्त: 9 बजे से 4 बजे तक होगा। शहर के जो भी रक्तदाता रक्त दान करना चाहते हैं वे आमत्रित आयोजित किया जाएगा। इन चार दिनों में लगभग एक लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिविर 1975-77 के आपातकाल में हजारों लोकतंत्र सेनानियों ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु यातनाएँ सही और जेलों में समय बिताया। आज उनके परिवार, विशेषकर युवा पीढ़ी, कई क्षेत्रों में पिछड़ेपन का सामना कर रही है। युवा संकल्प: इस स्थिति को बदलने की विश्वास में एक ठोस प्रयास है।

परियोजना के प्रमुख आयाम:



कौशल विकास प्रशिक्षण: कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, सिलाई, ब्लूटूथ पार्टर, फूट प्रोसेसिंग,

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि।

उद्यगिता प्रोत्साहन: व्यवसाय शुरू करने हेतु

परिवर्द्धन और संसाधन।

मानसिक सशक्तिकरण: आत्मविश्वास, नेतृत्व

विकास एवं सामाजिक सहभागिता।

रोजगार/स्व-रोजगार अवसर: सरकारी योजनाओं, बैंकों व निजी क्षेत्रों से जोड़ना।

परियोजना का संचालन लोकतंत्र रक्षक संघ के द्वारा किया जाएगा।

परिवर्द्धन और संसाधन।

परिवर्द्धन के संसाधनों से सहयोग की अपील की जाएगी।

हम मानते हैं – जब समाज साथ चलता है, तो

परिवर्तन स्थायी होता है।

परियोजना के द्वारा एक योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। संघ ने समाज के सभी वर्गों, मीडिया, जनप्रतिनिधियों, एस्ट्रक्चरल स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत शक्ति ही क्यों ना उठानी पड़े। इस मॉडल को भविष्य में अन्य राज्यों में भी लागू करने का लक्ष्य है।

समाज से अपील: यह

जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने में चेहरे से पहचान की पद्धति के महत्व को ऐक्यांकित किया।

पीआईबी

